नीलावती और अन्य

बनाम

एम. नटराजन और अन्य

30 नवंबर, 1979

[एस. मुर्तजा फजल अली, पी.एस. कैलासम और ए.डी. कौशल, जेजे.]

देय न्यायालय शुल्क - देय न्यायालय शुल्क के प्रश्न पर वाद में लगाए गए आरोपों में विचार किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम – धारा 37 – वाद पत्र में आरोप है कि वादी संयुक्त कब्जे में थे और राहत विभाजन और अलग कब्जे के लिए थी - देय सही न्यायालय शुल्क धारा 37(ii) द्वारा शासित होता है, न कि 37(i) द्वारा।

वादी, अपीलार्थियों ने कानून के अनुसार विभाजन और अपने व्यक्तिगत हिस्से के अलग कब्जे के लिए एक वाद दायर किया और तमिलनाडु न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 37(ii) के तहत निर्धारित दरों पर न्यायालय शुल्क का भुगतान किया। एक विशिष्ट आरोप था कि वे संयुक्त कब्जे में थे। विचारण न्यायालय ने वाद का फैसला सुनाया लेकिन वादी अपीलार्थियों को अधिनियम की धारा 37(ii) के तहत न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया। चूंकि न्यायालय की फीस में अंतर का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में दो अपीलें दायर की गईं, एक इस फैसले के खिलाफ कि वे न्यायालय शुल्क (धारा 37(1) के तहत संपत्ति का बाजार मूल्य) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और दूसरी वाद को खारिज करने के आदेश के खिलाफ। उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों को एक साथ सुना और

प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों के इस तर्क को स्वीकार करते हुए अपीलों का निस्तारण किया कि न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 37(I) के तहत वाद पत्र और अपील के ज्ञापन दोनों पर देय है।

विशेष अनुमति द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: 1. यह सुस्थापित कानून है कि न्यायालय शुल्क के प्रश्न पर वाद में लगाए गए आरोप के आलोक में विचार किया जाना चाहिए और इसका निर्णय लिखित बयान में याचिकाओं या गुण-दोष के आधार पर वाद के अंतिम निर्णय से प्रभावित नहीं हो सकता है। वाद पत्र में निहित सभी भौतिक आरोपों का अर्थ लगाया जाना चाहिए और समग्र रूप से लिया जाना चाहिए। [311 डी-ई]

तत्काल मामले में: (क) समग्र रूप से वाद को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि पूरे वाद पत्र में, वादी/अपीलार्थियों ने जोर देकर कहा है कि वे संयुक्त अधिकार में थे और इसलिए सभी पैराग्राफ में पढ़ने वाली उच्च न्यायालय की टिप्पणी केवल एक औपचारिक बयान है जो वैधानिक भाषा को दोहराती है, सही नहीं है। (ख) यह याचिका कि उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया था, बेदखल करने के बराबर नहीं होगी। वादी के खिलाफ सबसे खराब स्थिति में वाद पत्र को पढ़कर, केवल इतना ही समझा जा सकता है कि चूंकि वादी को आय का उनका हिस्सा नहीं दिया गया था, इसलिए वे संयुक्त कब्जे में नहीं रह सकते थे। यह कथन कि उन्हें उनकी आय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, अधिकार से बाहर होने के बराबर नहीं होगा। वाद-पत्र में दिए गए कथन को यह कहते हुए नहीं समझा जा सकता है कि वादी के कब्जे में नहीं था। वास्तव में, प्रतिवादियों ने वाद को यह कहते हुए समझा कि वादी मुकदमे की संपत्तियों के संयुक्त कब्जे में हैं। लिखित बयान के पैराग्राफ 18 में प्रतिवादियों ने दलील दी कि वादी ने वाद तैयार किया है जैसे कि वे संयुक्त कब्जे में हैं और मुकदमे की संपत्तियों का आनंद ले रहे हैं। यह कहते हुए कि वादी कब्जे से बाहर थे, प्रतिवादियों ने कहा:

"जबकि ऐसा है, यह आरोप कि वे वाद की संपत्तियों के संयुक्त कब्जे में हैं, सही नहीं है।" केवल यह तथ्य कि वादी को आय के अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया गया था या वे वास्तविक कब्जे में नहीं थे, वादी को संयुक्त कब्जे से बाहर रखने के बराबर नहीं होगा, जिसके वे कानूनी रूप से हकदार हैं। [1311डी, 312 बी-एफ]

एस. आरएम. एआर. एस. श्री कैथन्ना चेट्टियार बनाम एस. आरएम. एआर. आरएम रामानाथेन चेट्टियार, [1958] एससीआर 1021 @पीपी 1031-32; अनुसरण किया गया।

2. तमिलनाडु न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 37(1) के तहत, विभाजन के वादों से संबंधित, न्यायालय शुल्क देय है, यदि वादी को संपत्ति के कब्जे से "बाहर" रखा गया है। कानून का सामान्य सिद्धांत यह है कि सह-मालिकों के मामले में, एक का कब्जा सभी के कानूनी कब्जे में है, जब तक कि निष्कासन या बहिष्करण साबित न हो जाए। कानून में संयुक्त कब्जे में बने रहने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वादी को संपत्ति के पूरे या हिस्से के वास्तविक कब्जे में होना चाहिए। समान रूप से यह आवश्यक नहीं है कि उसे संपत्ति से हिस्सा या कुछ आय मिल रही हो। जब तक किसी हिस्से पर उसका अधिकार और संयुक्त रूप से संपत्ति की प्रकृति विवादित नहीं है, तब तक कानून यह मानता है कि वह संयुक्त कब्जे में है जब तक कि उसे ऐसे कब्जे से बाहर नहीं रखा गया है, इससे पहले कि वादी को अधिनियम की धारा 37(1) के तहत न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए इस आधार पर बुलाया जा सके कि उन्हें कब्जे से बाहर रखा गया था, यह आवश्यक है कि वाद पत्र में एक स्पष्ट और विशिष्ट दावा होना चाहिए कि उन्हें संयुक्त कब्जे से "बाहर" रखा गया था, जिसके वे कानून में हकदार हैं। [313 बी, डी-एफ]

तत्काल मामले में:

(क) वादपत्र में यह कथन कि वादी संयुक्त कब्जे में नहीं रह सकता क्योंकि उसे संयुक्त परिवार की संपत्ति से कोई आय नहीं दी गई थी, उसे कब्जे से बाहर रखने के बराबर नहीं होगा। [313 एफ-जी]

(ख) वादीगण जो प्रतिवादियों की बहनें हैं, उन्होंने संयुक्त परिवार के सदस्य होने का दावा किया और यह आरोप लगाते हुए विभाजन के लिए प्रार्थना की कि वे संयुक्त कब्जे में हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 30) की धारा 6 के प्रावधान के तहत, वादी उस पुरुष हिंदू की बेटियां हैं, जिनकी अधिनियम के प्रारंभ के बाद मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु के समय मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज था, जिन्होंने अधिनियम के तहत हस्तांतरण द्वारा ब्याज अर्जित किया था। वादी जिस संपत्ति के हकदार हैं, वह अविभाजित 'संयुक्त पारिवारिक संपत्ति' है, हालांकि शब्द के सख्त अर्थ में नहीं। [313 सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3530/1979

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ए.एस. संख्या 924/74 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 2-2-1979 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा अपील।

के. एस. राममूर्ति, पी. एन. रामलिंगम और ए.टी.एम. संपत, अपीलार्थी की ओर से।

के. राम कुमार और के. जयराम, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

कैलासम, न्यायाधिपति.-

विशेष अनुमति द्वारा अपील में अपीलार्थी मुकदमे में वादी 1 से 5 हैं। वादी 1 से 5 बहनें हैं और प्रतिवादी 1 से 2 उनके भाई हैं। तीसरा प्रतिवादी उनकी अविवाहित बहन है। वे स्वर्गीय मुथुकुमारस्वामी गौंडर के बच्चे हैं, जो अपने पिता वनवराय गौंडर को

छोड़कर 20-12-1962 पर निर्वसीयत रूप से मर गए, जो 5-3-1972 को अपनी मृत्यु तक हिंदू अविभाजित संयुक्त परिवार के प्रमुख के रूप में सभी पैतृक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का प्रबंधन कर रहे थे। वादियों ने दावा किया कि मुथुकुमारस्वामी गौंडर की मृत्यु पर संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उनका एक तिहाई हिस्सा उनके बेटों और बेटियों को हस्तांतरित किया गया, उनके बेटे, प्रतिवादी 1 और 2 ने जन्म से पारिवारिक संपत्ति के एक तिहाई हिस्से में एक तिहाई हिस्सा लिया और शेष में मुथुकुमारस्वामी गौंडर के सभी बेटे और बेटियां समान हिस्सा ले रही थीं। वादी ने वनवराय गौंडर और उनके अन्य बेटों के साथ संपत्तियों के संयुक्त कब्जे में होने का दावा किया। इसी तरह वनवराय गौंडर की मृत्यु पर, पारिवारिक संपत्तियों में उनका एक तिहाई हिस्सा उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया गया, वादी और प्रतिवादी 1 से 3 कुछ शेयरों के हकदार थे। वाद पत्र में दावा किया गया है कि प्रत्येक वादी स्वर्गीय मुथुकुमारस्वामी गौंडर के उत्तराधिकारी के रूप में और उनके दादा स्वर्गीय वनवराय गौंडर के उत्तराधिकारी के रूप में वाद की संपत्तियों में हिस्सेदारी का हकदार है। प्रत्येक वादी ने दावा किया कि वह अपने पिता मुथुकुमारस्वामी गौंडर के उत्तराधिकारी के रूप में वाद की संपत्तियों में 1/72 हिस्सेदारी और उनके दादा वनवराय गौंडर के उत्तराधिकारी के रूप में 1/96 हिस्सेदारी की भी हकदार थी। वाद पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि वनवराय गौंडर की मृत्यु के बाद से, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वादी को आय का अपना हिस्सा देने में विफल रहे और वादी संयुक्त कब्जे में नहीं रह सके। वादी बार-बार विभाजन की मांग कर रहे थे और प्रतिवादी 1 से 6 बच रहे थे। वादी ने दावा किया कि सह-मालिक के रूप में प्रत्येक वादी मुकदमे की संपत्तियों के संयुक्त कब्जे में है और यह कार्रवाई संयुक्त कब्जे को अलग कब्जे में बदलने के लिए की गई थी जहां तक वादी के शेयरों का संबंध है। न्यायालय शुल्क और अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए, वादी ने संपत्ति के अपने हिस्से का मूल्यांकन किया और 200 रुपये न्यायालय शुल्क का भुगतान तमिलनाडु न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत किया। जिस राहत के लिए प्रार्थना की गई थी, वह संपत्तियों के विभाजन और उनके अलग हिस्से के आवंटन, खातों और अन्य राहतों के लिए थी।

लिखित बयान में, प्रतिवादिगण 1 लगायत 2, भाइयों ने तर्क दिया कि मुथुकुमारस्वामी गौंडर के जीवनकाल के दौरान वर्ष 1946 में संपत्तियों को विभाजित किया गया था और मुथुकुमारस्वामी अलग से संपत्तियों का उपभोग ले रहे थे। वादियों के कब्जे के संबंध में, प्रतिवादीगण 1 लगायत 3, विरोध करने वाले प्रतिवादीगण ने लिखित बयान के पैराग्राफ 18 में इस प्रकार आरोप लगाया: -

> "जैसा कि वाद बनाया गया है वह कानून द्वारा संधार्य नहीं है। वादी ने वाद इस तरह वाद तैयार किया है जैसे कि वे संयुक्त कब्जे में हैं और वाद की संपत्तियों का उपभोग कर रहे हैं। वादी कब्जे से बाहर हैं और वे अलग-अलग गाँवों में रह रहे हैं। जबकि यह आरोप सही नहीं है कि वे वाद की संपत्तियों के संयुक्त कब्जे में हैं। वादी को न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 37(i) के तहत न्यायालय शुल्क का भुगतान करना चाहिए था न कि अधिनियम के 37(ii) के तहत। उन्हें वाद की संपत्तियों के बाजार मूल्य पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करना चाहिए था और जब तक बाजार दर पर न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, वे किसी भी हिस्से का दावा करने के हकदार नहीं हैं।"

वाद का विचरण करने वाले अधीनस्थ न्यायाधीश ने न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत आवश्यक न्यायालय शुल्क के संबंध में कोई प्रारंभिक विवाधक नहीं बनाया, लेकिन सभी मुद्दों को एक साथ आज़माने के लिए आगे बढ़े। अधीनस्थ न्यायाधीश ने बी अनुसूची संपत्तियों में वादी के 1/72 हिस्से के विभाजन और

कब्जे के लिए, और पोल्लाची में भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए गए कुछ शेयरों और ज्ञानम्बिका मिल्स में हिस्से के लिए, न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 37(i) के तहत वादी द्वारा न्यायालय शुल्क के भुगतान पर प्रारंभिक डिक्री प्रदान की। न्यायालय ने न्यायालय शुल्क के भुगतान के लिए 15-2-1973 तक का समय दिया। चूंकि न्यायालय की फीस का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 7-2-1974 के निर्णय से वाद को खारिज कर दिया।

वादी ने दो अपीलें दायर की – ए.एस.संख्या 811/1975 अधीनस्थ न्यायाधीश के फैंसले के खिलाफ जिसमे न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 37(1) के तहत संपत्ति के बाजार मूल्य पर न्यायालय शुल्क के भुगतान के लिए वादी को उत्तरदायी ठहराया गया और ए.एस.संख्या 924/1974 वाद ख़ारिज करने के आदेश के खिलाफ।

उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों को एक साथ सुना और एक सामान्य निर्णय द्वारा उनका निस्तारण किया। जब अपीलों पर विचार किया गया, तो प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि न्यायालय शुल्क का भुगतान धारा 37(1) के तहत और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के ज्ञापन पर भी किया जाना चाहिए था और चूंकि उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया और कहा कि वादी तमिलनाडु न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 37(1) के तहत न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से वाद के पैराग्राफ 12 पर भरोसा किया जो इस प्रकार हैः -

> "वनवराय गौंडर की मृत्यु के बाद से प्रतिवादी 1 लगायत 6 वादी को आय का अपना हिस्सा देने में विफल रहे और वादी संयुक्त कब्जे में नहीं रह सके। इसलिए, वादी बार-बार विभाजन की मांग कर रहे थे

और प्रतिवादी 1 लगायत 6 बच रहे थे। तीसरी वादी ने अपने अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी 1,2 और 5 को एक नोटिस भेजा, जिस पर तीसरी वादी को झूठे और असमर्थनीय आरोपों वाले जवाब प्राप्त हुए।"

उच्च न्यायालय यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि जबकि यह कथन कि वादी का प्रतिवादियों के साथ संयुक्त कब्ज़ा था, जो कि वादी के अन्य पैराग्राफों में होता है, केवल वैधानिक भाषा को दोहराने वाला एक औपचारिक बयान है, वादी के पैराग्राफ 12 में निहित कथन एक बयान का गठन करता है उस संदर्भ में तथ्य जिसमें अनुच्छेद 12 आता है और परिणामस्वरूप वादपत्र के अनुच्छेद 13 में एक स्पष्ट कथन है कि वादी संयुक्त कब्जे में नहीं रह सकता है और यही कारण था कि वे बार-बार विभाजन की माँग करते रहे। यदि ऐसा है, तो वाद की तारीख को, वादी कब्जे में नहीं थे। उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत न्यायालय शुल्क देय है।

समग्र रूप से वाद को पढ़ने पर, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। यह सुस्थापित कानून है कि न्यायालय शुल्क के सवाल को वाद में लगाए गए आरोप के आलोक में विचार किया जाना चाहिए और इसका निर्णय लिखित बयान में याचिकाओं या गुण-दोष पर वाद के अंतिम निर्णय से नहीं हो सकता है। वाद पत्र में निहित सभी भौतिक आरोपों का अर्थ लगाया जाना चाहिए और एस.आरएम. एआर. एसपी. आर. एस. पी. सतप्पा चेट्टियार बनाम एस. राम आर। आर. एम. रामनाथन चेट्टियार के माध्यम से समग्र रूप से लिया जाना चाहिए। पैराग्राफ 5 में वाद पत्र में कहा गया है कि मुथुकुमारस्वामी गौंडर की निर्वसीयत और अविभाजित मृत्यु हो गई और मुथुकुमारस्वामी के पिता वनवराय गौंडर अपनी मृत्यु तक हिंदू अविभाजित संयुक्त परिवार के प्रमुख के रूप में सभी पैतृक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का प्रबंधन कर रहे थे। पैराग्राफ 8 में वादी ने कहा कि मुथुकुमारस्वामी गौंडर की मृत्यु पर संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उनका एक तिहाई हिस्सा उनके बेटों और बेटियों

को हस्तांतरित कर दिया गया। इसने आगे आरोप लगाया कि वादी वनवराय गौंडर और उनके अन्य बेटों के साथ संपत्तियों के संयुक्त कब्जे में थे। पैराग्राफ 9 में कहा गया है कि प्रत्येक वादी स्वर्गीय मुथुकुमारस्वामी गौंडर के उत्तराधिकारी और स्वर्गीय वनवराय गौंडर के उत्तराधिकारी के रूप में वाद की संपत्तियों में हिस्सेदारी के हकदार हैं। पैराग्राफ 11 में, यह कहा गया है कि वनवराय गौंडर की मृत्यु के बाद से 1 लगायत 6 प्रतिवादियों को संपत्तियों से आय प्राप्त हो रही है और वे वादी को जवाबदेह हैं। पैराग्राफ 12 में, यह कहा गया है कि वनवराय गौंडर की मृत्यु के बाद से प्रतिवादी 1 लगायत 6 वादी को आय का अपना हिस्सा देने में विफल रहे और वादी संयुक्त कब्जे में नहीं रह सके। इसलिए वादी ने विभाजन की मांग की और प्रतिवादी 1 लगायत 6 बच रहे थे। पैराग्राफ 13 में फिर से यह दावा किया गया है कि सह-मालिक के रूप में प्रत्येक वादी मुकदमे की संपत्तियों के संयुक्त कब्जे में है और यह कार्रवाई संयुक्त कब्जे को अलग कब्जे में बदलने के लिए की गई है जहां तक वादी के शेयरों का संबंध है। पूरे वाद के दौरान, वादी ने दावा किया है कि वे संयुक्त कब्जे में हैं। हम उच्च न्यायालय से सहमत होने में असमर्थ हैं कि सभी अनुच्छेदों में पाठ केवल वैधानिक भाषा को दोहराने वाला एक औपचारिक बयान है। उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 12 में जिस तर्क पर भरोसा किया गया था, उसमें कहा गया है कि प्रतिवादी 1 लगायत 6 वादी को आय का अपना हिस्सा देने में विफल रहे और वादी संयुक्त कब्जे में नहीं रह सके। यह दलील कि उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया, बेदखल करने के बराबर नहीं होगी। वादी के खिलाफ सबसे खराब स्थिति में वाद पत्र को पढ़कर, केवल इतना ही समझा जा सकता है कि चूंकि वादी को आय का उनका हिस्सा नहीं दिया गया था, इसलिए वे संयुक्त कब्जे में नहीं रह सकते थे। यह कथन कि उन्हें अपनी आय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, अधिकार से बाहर होने के बराबर नहीं होगा। वाद-पत्र में दिए गए कथन को यह कहते हुए नहीं समझा जा सकता है कि वादी के कब्जे में नहीं था। वास्तव में, प्रतिवादियों ने वाद को यह कहते हुए समझा कि वादी मुकदमे की संपत्तियों के संयुक्त

कब्जे में हैं। लिखित कथन के पैराग्राफ 18 में प्रतिवादियों ने दलील दी कि वादी ने मुकदमे को इस तरह तैयार किया है जैसे कि वे मुकदमे की संपत्तियों पर संयुक्त कब्जे और आनंद में हैं। यह दावा करते हुए कि वादी कब्जे से बाहर हैं, प्रतिवादियों ने कहा: "हालांकि ऐसा है, यह आरोप कि वे मुकदमे की संपत्तियों पर संयुक्त कब्जे में हैं, सही नहीं है"।

विचारण न्यायालय ने वाद के पैरा 12 के पाठ पर कोई निर्भरता नहीं रखी है, जिस पर उच्च न्यायालय का निर्णय आधारित है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर पाया कि वादी ने कभी भी मुकदमे की संपत्तियों का उपयोग नहीं लिया। यह निष्कर्ष पर्याप्त नहीं है, केवल इस तथ्य के लिए कि वादी को आय के अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया गया था या वे वास्तविक भौतिक कब्जे में नहीं थे, वादी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। संयुक्त अधिकार से बाहर रखा गया है जिसके वे कानूनी रूप से हकदार हैं। समग्र रूप से वाद पर विचार करने और इसे इसका स्वाभाविक अर्थ देने पर, हम उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं।

तमिलनाडु न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 37 विभाजन वाद से संबंधित है। धारा 37 इस प्रकार प्रदान करती हैः -

> 37(1) विभाजन और संयुक्त परिवार की संपत्ति या संयुक्त रूप से या सामान्य रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति के हिस्से के अलग कब्जे के लिए एक वाद में, एक वादी द्वारा जिसे ऐसी संपत्ति के कब्जे से बाहर रखा गया है, शुल्क की गणना वादी के हिस्से के बाजार मूल्य पर की जाएगी।
>
> 37(2) विभाजन के लिए एक वाद में और संयुक्त परिवार की संपत्ति या संपत्ति के अलग कब्जे में, संयुक्त रूप से या सामान्य रूप से एक

वादी के स्वामित्व में, जो ऐसी संपत्ति के संयुक्त कब्जे में है, शुल्क का भुगतान निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

यह देखा जाएगा कि न्यायालय शुल्क धारा 37(1) के तहत देय है यदि वादी को संपत्ति के कब्जे से 'बाहर' रखा गया है। वादियों, जो प्रतिवादियों की बहनें हैं, ने संयुक्त परिवार के सदस्य होने का दावा किया और विभाजन के लिए प्रार्थना की, यह आरोप लगाते हुए कि वे संयुक्त कब्जे में हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 30) की धारा 6 के प्रावधान के तहत वादी उस पुरुष हिंदू की बेटियां हैं, जिनकी मृत्यु के समय मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज होने के कारण अधिनियम के तहत हस्तांतरण द्वारा ब्याज प्राप्त किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि वादी हिस्से के हकदार हैं। वादी जिस संपत्ति के हकदार हैं, वह अविभाजित 'संयुक्त पारिवारिक संपत्ति' है। हालांकि शब्द के सख्त अर्थ में नहीं। कानून का सामान्य सिद्धांत यह है कि सह-मालिकों के मामले में, एक का कब्जा सभी के कानूनी कब्जे में है, जब तक कि निष्कासन या बहिष्करण साबित न हो जाए। कानून में संयुक्त कब्जे में बने रहने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वादी को पूरी या संपत्ति के हिस्से के वास्तविक कब्जे में होना चाहिए। समान रूप से यह आवश्यक नहीं है कि उसे संपत्ति से हिस्सा या कुछ आय मिल रही हो। जब तक किसी हिस्से पर उसका अधिकार और संयुक्त रूप से संपत्ति की प्रकृति विवादित नहीं है, तब तक कानून यह मानता है कि वह संयुक्त कब्जे में है जब तक कि उसे इस तरह के कब्जे से बाहर नहीं रखा जाता है। इससे पहले कि वादी को अधिनियम की धारा 37(1) के तहत इस आधार पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए बुलाया जा सके कि उन्हें कब्जे से बाहर रखा गया था, यह आवश्यक है कि वाद पत्र को पढ़ने पर, वाद पत्र में एक स्पष्ट और विशिष्ट दावा होना चाहिए कि उन्हें संयुक्त कब्जे से "बाहर" रखा गया था, जिसके वे कानूनी रूप से हकदार हैं। संयंत्र में यह कथन कि वादी संयुक्त कब्जे में नहीं रह सकता क्योंकि उसे संयुक्त परिवार की संपत्ति से कोई आय नहीं दी गई थी, उसे कब्जे से बाहर रखने के बराबर नहीं होगा।

हम वाद में एक स्पष्ट और विशिष्ट स्वीकारोक्ति को पढ़ने में असमर्थ हैं कि वादी को कब्जे से बाहर रखा गया था।

परिणामस्वरूप अपील को लागत के साथ स्वीकार किया जाता है। जैसा कि हमने पाया है कि विचारण न्यायालय ने वादी को धारा 37(1) के तहत न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देने में गलती की थी, बी अनुसूची की संपत्तियों और पोल्लाची में भारतीय स्टेट बैंक में जमा शेयरों और ज्ञानम्बिका मिल्स में हिस्सेदारी के विभाजन और कब्जे के लिए प्रारंभिक डिक्री की पुष्टि की जाती है। न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 37(1) के तहत न्यायालय शुल्क के भुगतान के बारे में विचारण न्यायालय के निर्देश और ए.एस. संख्या 924/1974 और ए.एस. 811/75 में उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाता है।

एस.आर.

अपील स्वीकार की गई।

(1) [1958] एस.सी.आर. 1021 पेज 1031-32

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****